यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

21 जून, 2019

"प्रमुख केंद्रीय बैंकों की ओर से किए गए बदलाव के कारण वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ गया है।"

अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के सामान्य होने के दिन खत्म हो सकते हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बुधवार को समाप्त हुई दो दिवसीय नीति बैठक के बाद, अपनी संघीय निधियों की दर को 2.25% से 2.50% की सीमा तक अपरिवर्तित रखा और साथ ही उधार की लागतों पर सख्त होने का संदर्भ छोड़कर नीति को आसान बनाने के लिए अपनी तत्परता का संकेत दिया।

फेड के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने सुझाव दिया कि केंद्रीय बैंक अमेरिकी आर्थिक विकास के लिए विभिन्न खतरों से निपटने के लिए निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। विशेष रूप से, उन्होंने व्यापार के मोर्चे पर अनिश्चितता और अमेरिका तथा अन्य अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने की अपनी क्षमता पर अधिक ध्यान दिया।

इस महीने जापान में होने वाले G-20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात होने वाली है और 31 जुलाई को अपनी अगली बैठक के समापन पर फेड का निर्णय ट्रम्प-शी वार्ता के परिणाम पर अच्छी तरह से केन्द्रित हो सकता है।

फेड का यह रुख यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी, ECB) के अध्यक्ष मारियो ड्रैगी के ठीक उस संकेत के बाद आया, जहाँ उन्होंने कहा कि यदि मुद्रास्फीति बढ़ने में विफल रही, तो ईसीबी दर में कटौती और बॉण्ड खरीद का सहारा ले सकती है। हालांकि, उनके लहजे में बदलाव साफ है। फेडरल रिजर्व ने 2015 में अपनी नीति के सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी, जिससे कई उभरती बाजार मुद्राएं संकट में आ गईं। लेकिन सामान्यीकरण के बस कुछ साल बाद और शून्य से ऊपर वास्तविक ब्याज दरों के साथ, केंद्रीय बैंक पहले से ही दरों में संभावित कटौती के बारे में बात कर रहे हैं, यदि अर्थव्यवस्था इसकी मांग करती है।

यह दोतरफा मोड़ अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनाव के कारण वैश्विक आर्थिक मंदी के बढ़ते खतरे का संकेत देता है। यह इस बात का भी संकेत हो सकता है कि केंद्रीय बैंक श्री ट्रम्प जैसे राजनेताओं के दबाव को बढ़ा रहे हैं, जो फेड की आलोचना में मुखर रहे हैं।

हालांकि, महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती करेंगे या नहीं, बल्कि यह है कि परिणामी दरों में कटौती वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त होगी या नहीं। यह विशेष रूप से ऐसे समय में है जब व्यापार युद्धों ने वस्तुओं एवं सेवाओं की आवाजाही पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है।

इसके अलावा, वर्तमान में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वास्तविक ब्याज दर शून्य से अधिक नहीं है, केंद्रीय बैंकों को दर में कटौती करने और अर्थव्यवस्था में सीधे पैसा लगाने के लिए अन्य अपरंपरागत नीति उपायों को ढूँढ़ना पड़ सकता है। लेकिन समस्या यह है कि यह भी सफलता सुनिश्चित नहीं कर सकता क्योंकि मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता बढ़ते कर्ज के स्तर के साथ घट रही है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहजता के साथ बदलाव के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के लिए रुपये में इस तरह की कटौती के प्रभाव के बारे में चिंता किए बिना आक्रामक रूप से दरों में कटौती करना आसान हो जाएगा। हालांकि, विकास को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक सुधारों के एक नए दौर की आवश्यकता हो सकती है।

जी-20

क्या है?

- सितंबर, 1999 में जी-7 देशों के वित्त मंत्रियों ने जी-20 का गठन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के तौर पर किया था। यह मंच अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के साथ ब्रेटन वुड्स संस्थागत प्रणाली की रूपरेखा के भीतर आने वाले व्यवस्थित महत्वपूर्ण देशों के बीच अनौपचारिक बातचीत एवं सहयोग को बढ़ावा देता है।
- यह समूह (जी-20) अपने सदस्यों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और कुछ मुद्दों पर निर्णय करने के लिए प्रमुख मंच है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। जी-20 के नेता वर्ष में एक बार साथ मिलते हैं और बैठक करते हैं।
- इसके अलावा, वर्ष के दौरान, देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार लाने, वित्तीय नियमन में सुधार लाने और प्रत्येक सदस्य देश में जरूरी प्रमुख आर्थिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठक करते रहते हैं।
- इन बैठकों के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और विशेष मुद्दों पर नीतिगत समन्वय पर काम करने वाले कार्य समूहों के बीच वर्ष भर चलने वाली बैठकें भी होती हैं।
- ये देश विश्व के आर्थिक उत्पादन के 85 फीसदी का और जनसंख्या के 60 फीसदी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व बैंक और आईएमएफ के प्रमुख भी इस संगठन के सदस्य हैं। जी-20 की पहली बैठक दिसंबर, 1999 में बर्लिन में हुई थी।

स्थापना और शुरुआत

- जी-20 की शुरुआत, 1999 में एशिया में आए वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक के तौर पर हुई थी। वर्ष 2008 में जी-20 के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और समूह ने वैश्विक वित्तीय संकट का जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- इसकी निर्णायक और समन्वित कार्रवाई ने उपभोक्ता और व्यापार में भरोसा रखने वालों को शक्ति दी तथा आर्थिक सुधार के पहले चरण का समर्थन किया। वर्ष 2008 के बाद से जी-20 के नेता आठ बार बैठक कर चुके हैं।
- जी-20- वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन के साथ मिलकर काम करता है। कई अन्य संगठनों को भी जी-20 की प्रमुख बैठकों में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

जी-20 के सदस्य देश

- जी-20 के सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का करीब 85 फीसदी, वैश्विक व्यापार के 75 फीसदी और विश्व की आबादी के दो-तिहाई से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सदस्य देशों के नाम

- अर्जेंटीना,ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ

क्यों पड़ी जी-20 जैसे मंच की जरूरत

- जी-20 का गठन उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ विचार-विमर्श एवं समन्वय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था।
- विश्व के सात प्रमुख औद्योगिक देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे पहले जी-20 में शामिल हुए।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1- G-20 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. G-20 का स्थायी स्टाफ नहीं होता और न ही इसका कोई हेड क्वार्टर है। यह सिर्फ एक फोरम है।
2. G-20 के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन 2008 में किया गया था।
3. 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया जाएगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1, 2 और 3 (b) केवल 3
(c) 2 और 3 (d) केवल 2

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements regarding G-20-

1. There is no permanent staff of G-20 and it has no head quarters. This is just a forum.
2. The first summit of the G-20 was conducted in 2008.
3. 15th Summit will be held in Riyadh, Saudi Arabia.

Which of the above statements is/are correct?

(a) 1, 2 and 3 (b) Only 3
(c) 1 and 3 (d) Only 2

Expected Questions (Mains Exams)

प्रश्न: अमेरिका और चीन के मध्य बढ़ रहा व्यापारिक तनाव क्या विश्व अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी की ओर ले जाएगा? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

Q. Will the growing tension of trade war between the US and China lead to the global economic slowdown? Critically examine. (250Words)

नोट : 20 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d) होगा।

Committed To Excellence